प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 15 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 4 – 11 अप्रैल 2022 मूल्य पांच रूपए

इन्वेस्टर मीट के दावों के बीच सीमेंट उद्योग की भ्रूण हत्या के मायने

→ जुलाई 2019 में निदेशक से आये पत्र को फाईनल करने में डेढ़ वर्ष का समय क्यों लगा?

→ क्या इस दौरान यह फाइल सचिव तक ही रही या आगे भी गयी

→ इसी तरह का अंत एशियन और डालमिया के प्लांट का भी क्यों हुआ?

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब 2018 में अपना पहला बजट भाषण सदन में पढ़ा था तब उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। प्रदेश को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए औद्योगिक विस्तार के माध्यम से निवेश जुटाने की योजना बनायी गयी। इसके लिये धर्मशाला में 2019 में बड़े स्तर पर इन्वेस्टर मीट आयोजित की गयी। इस मीट में एक लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने का दावा किया। लेकिन मार्च 2020 में ही लॉकडाउन लगा दिये जाने से यह दावा पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। कोविड के कारण इसके लिए सरकार को ज्यादा दोषी नहीं ठहराया जा सकता यह स्वाभाविक है। लेकिन जब मार्च 2014 में एकल खिड़की योजना में क्लियर किये गये सीमेंट उद्योग को 2021 में भ्रूण हत्या का शिकार बनना पड़ जाये तो पूरी सरकार की नीयत और नीति का आकलन बदल जाता है।

स्मरणीय है कि मार्च 2014 में स्व. वीरभद्र सिंह की सरकार ने शिमला के चौपाल में रिलायंस उद्योग के लगने वाले 34 करोड़ के एक सीमेंट प्लांट की स्थापना की एकल खिड़की योजना के तहत अनुमति प्रदान की थी। इस अनुमति के बाद प्लांट की स्थापना से जुड़े अन्य कार्य शुरू किये गये। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निदेशक उद्योग ने जुलाई 2019 में यह मामला एल ओ आई जारी किये जाने के लिये सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली कारवाई के लिये भेज दिया। लेकिन जुलाई 2019 में सचिवालय में आये इस प्रस्ताव पर जनवरी 2021 तक एल ओ आई जारी नहीं हो सका। इसी बीच रिलायंस से यह उद्योग आर सी सी पी एल प्राइवेट लिमिटेड ने ले लिया था। एल ओ आई का आवेदन रिलायंस ने दायर कर दिया हुआ था। लेकिन इस कंपनी को यह एल ओ आई 20 – 01 – 2021 को प्राप्त हुआ। इसी बीच भारत सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट मार्च में संशोधित किये जाने के समाचार आ चुके थे। इन समाचारों के परिदृश्य में कंपनी को पर्याप्त समय रहते एल ओआई की जगह ग्रांट ऑर्डर चाहिये था। कंपनी ग्रांट ऑर्डर की पैरवी में लग गयी जो उसे 23 – 03 – 2021 को मिला। परन्तु एम एम डी आर एक्ट का संशोधन 28 – 03 – 2021 से लागू हो गया।

ऐसे में यह स्वभाविक है कि जिस उद्योग में करीब 4000 करोड़ का निवेश होना हो और करीब 400 लोगों को रोजगार मिलना हो उसे 23 – 03 – 2021 को ग्रांट ऑर्डर हासिल करके 28 – 03 – 2021 तक 5 दिन में अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता। इसमें प्रदेश को हर वर्ष हजारों करोड़ का नुकसान हो गया और सैकड़ों लोग रोजगार से वंचित रह गये हैं। क्योंकि यह उद्योग पैदा होने से पहले ही भ्रुण हत्या का शिकार बना दिया गया। एक ओर जयराम सरकार इसी प्रशासन के सहारे इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन करके निवेशकों को आमंत्रित कर रही है और दूसरी ओर उसी के सचिवालय में उसी की नाक के नीचे इतने बड़े निवेश तथा निवेशक के साथ इस तरह का अनुभव घट जाये तो इसका आम आदमी में सरकार को लेकर क्या संदेश जायेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

कंपनी ने सरकार के इस व्यवहार को लेकर मीडिया के कुछ लोगों को अपनी पीड़ा ब्यान करते हुये जो खुलासा किया है वह पूरे प्रशासन को बुरी तरह से बेनकाब कर देता है। उनकी पीड़ा के कुछ तथ्य पाठकों और सरकार के सामने भी आने चाहिये। शायद इसी नीयत से कंपनी मीडिया तक पहुंची है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 17 – 07 – 2019 को इस मामले की फाइल निदेशक से ए सी एस उद्योग को एल ओ आई जारी करने के लिए आयी। एल ओ आई 20 – 01 – 2021 को जारी हुआ और ग्रांट ऑर्डर 23 – 03 – 2021 को तथा 28 – 03 – 2021 को संशोधित एक्ट लागू हो गया। परिणाम स्वरूप सीमेंट प्लांट नहीं लग पाया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतना समय फाइल प्रोसैस करने में क्यों लग गया? कंपनी का आरोप है कि उनसे करोड़ों की रिश्वत मांगी गयी और उन्होंने दी भी कंपनी का तो यहां यहां तक आरोप है की गुड़गांव की सैक्टर 65 स्थित एम थ्री एम गोल्फ ऐस्टेट में एक फ्लैट भी किसी परिजन को दिया गया। कंपनी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उसने 2021 मार्च में घट चुके इस प्रकरण को क्यों अब मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने का फैसला लिया यह सब जांच का विषय है और सरकार को इसकी जांच करके सच्चाई सामने लानी चाहिये। क्योंकि मार्च 2014 में यह पलांट सिंगल विंडो में क्लियर किया जो मार्च 2021 में आकर इस तरह की हत्या का शिकार हो गया। चर्चा है कि ऐसा अन्त इसी उद्योग का अकेले नही हुआ हैं इसमें डालमिया और एशियन के प्लांट्स का भी यही अंत हुआ है।

इसी बीच यह शिकायत एक बृजलाल के माध्यम से पी एम ओ तक भी पहुंच गयी। बृजलाल शायद शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने वाकायदा यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भेज दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लेकर यह मामला राज्य सरकार को भेज दिया है। अब इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं इस पर सबकी निगाहें लग गयी हैं। चुनावों की पूर्व संध्या पर ऐसे मामलों का इस तरह से बाहर आना सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की राजनीतिक सेहत पर क्या असर डालता है यह देखना रोचक हो गया है। क्योंकि सीमेंट प्लांट जमीन पर नहीं उतर पाये हैं और सरकार इस पर खामोश रही है।

File No.104/52/2021-AVD-IA(Vol.3)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
AVD.IA Section

Room No.270, North Block, New Delhi
Dated, the 13th October, 2021

To

The Principal Secretary to CM,
Government of Himachal Pradesh,
Shimla- 171001.

Subject: **Complaint against Dr. Ram Subhag Singh, IAS (HP: 1987), Currently Chief Secretary.**

Sir,

The undersigned is directed to forward herewith a copy of a complaint dated 08.09.2021 received vide PMO ID NO. 5401635/2021-HR dated 20.09.2021 from Sh. Brij Lal against **Dr. Ram Subhag Singh, IAS (HP: 1987), Currently Chief Secretary**, for action as appropriate.

Encl: As stated.

Yours faithfully

Rupesh kuma

(Rupesh Kumar)
Under Secretary to the Government of India
23094799

Copy to :

1. Sh. Brij Lal, Dev Kunti Niwas lower, Tutu Shimla:-11.
2. Guard File, DOP&T, AVD-IA.

राज्यपाल ने जारी किया हि.प्र. विश्वविद्यालय का दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति दस्तावेज

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार दिव्यांग विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के मानवाधिकार संरक्षण के लिए नीति दस्तावेज जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई नीतियां भी इसमें शामिल की गई हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से

किया। दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति नामक इस दस्तावेज में उनसे संबंधित सभी प्रकार के कानूनी प्रावधानों, माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों और हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों का सार समाहित संबंधित सभी महाविद्यालयों में इस नीति को लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए नीति की आवश्यकता नहीं पड़ती है बल्कि सुझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति दस्तावेज कागज़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि यह जीवन की पद्धति बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार की नीति तैयार कर विश्वविद्यालय द्वारा देश में अग्रणी पहल की गई है और इससे समाज को भी सकारात्मक दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति दस्तावेज से न सिर्फ दिव्यांग विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी लाभ होगा।

इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल ने नीति दस्तावेज जारी करने के लिए राज्यपाल का स्वागत किया तथा दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय में किए गए प्रयासों और कार्यों की जानकारी दी। दिव्यांगजनों के लिए नोडल अधिकारी प्रो. अजय श्रीवास्तव ने नीति दस्तावेज तैयार करने और इस दिशा में सहयोग के लिए पूर्व कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार और वर्तमान कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने राष्ट्र निर्माण में सहयोग का आह्वान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों में सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति समाज को दिशा प्रदान करते हैं और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता करते हैं। राज्यपाल सोलन जिले के गण की सेर में स्थित माधव सृष्टि परिसर में माधव योग आश्रम के शिलान्यास समारोह के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि माधव सृष्टि योग जैसे परिसर समाज के लिए आवश्यक हैं क्योंकि यहां विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जिससे कई लोग इस पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अतीत से जुड़ें रहते हैं और इनका मानना है कि समाज में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं समाज में एक ऐसा भी वर्ग है, जिन्होंने समाज को जोड़ते हुए कर्म

को अपनाया।

माधव सृष्टि योगाश्रम के संस्थापक श्रीनिवास मूर्ति के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वह सही मायने में कर्म योग से जुड़ रहे और दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई समस्याएं हैं लेकिन एक कुशल व्यक्ति सामाजिक दायित्वों से जुड़कर समाज के निर्माण में योगदान देता है।

राज्यपाल ने कहा, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और समाज के कल्याण में योगदान देना हमारी जिम्मेदारी है तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।

उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र सदियों से अस्तित्व में है और हमने दुनिया को उदारता का विचार दिया है। हम आज भी विश्व को प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे योग आश्रम हमारे विचारों को दृढ़ करते हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने माधव योग आश्रम को अपने ऐच्छिक निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।

राज्यपाल ने मानव सृष्टि योग आश्रम के निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया।

इससे पहले, राज्यपाल ने सोलन जिले के गण की सेर में माधव सृष्टि परिसर में 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले माधव योग आश्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों और माधव सृष्टि परिसर के प्रकल्प द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा भी किया और इसमें विशेष रुचि दिखाई।

उत्तर क्षेत्र के प्रचारक संजीवन ने कहा कि योग का अर्थ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, प्रकृति और ईश्वर से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और आज फिर से योग का महत्व हर घर में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कार्य कुशलता योग से ही आती है और वर्तमान में योग के कारण ही विश्व में शांति स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि योग समाज का विषय है लेकिन जब यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।

योग भारती के संस्थापक श्रीनिवास मूर्ति ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और कहा कि योग आंतरिक शक्ति की पहचान है और इस आंतरिक शक्ति को जगाने वाले लोगों ने ब्रह्मांड की रक्षा की है। उन्होंने योग शक्ति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आत्मा का विकास तन, मन और बुद्धि के विकास से ही संभव है। उन्होंने भारतीय नस्ल की गाय के पालन और हवन प्रणाली की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 33वीं वार्षिक कोर्ट मीटिंग की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 33वीं विश्वविद्यालय कोर्ट मीटिंग आयोजित की गई।

राज्यपाल ने कहा कि पिछले दो वर्षो से कोरोना महामारी के कारण सभी कार्य बाधित रहे हैं, लेकिन

वर्तमान समय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रगति का ऐसा माध्यम है, जिससे हम समाज के विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों का वृहद नेटवर्क है तथा यहां कि शैक्षणिक दर भी बेहतर है। हमें इन सुविधाओं का लाभ सकारात्मक तरीके से उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों ने राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राज्यपाल ने कहा कि हि.प्र. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में देश भर के लिए एक उदाहरण बनकर उभर सकता है। राज्यपाल ने राज्य में नशीले पदार्थो के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षकों से इस दिशा में कार्य करते हुए युवा पीढ़ी को इस खतरे से बचाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डिग्री पूरी करने के बाद समाज से जुड़ाव के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

विश्वविद्यालय कोर्ट ने वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखा एवं वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की।

इस अवसर पर कार्यवाहक कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने राज्यपाल को गत वर्ष की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रबंधन, री-ऑरिएनटेशन और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सहित तीन मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विजन डॉक्युमेंट के अनुसार सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छोटा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और परिसर में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुनील शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने एम्बूलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन

से प्रदेश रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से दो एम्बूलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबन्धन समिति की सदस्य तथा प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी।

राज्यपाल एवं प्रदेश रेड क्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष ने कहा कि रेड क्रॉस पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की सहायता के लिए प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही है।

इन दो एम्बूलेंसों में से एक बेसिक लाइफ स्पोर्ट एम्बूलेंस मण्डी जिला तथा दूसरी एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बूलेंस राज्य रेड क्रॉस द्वारा संचालित की जाएगी। यह एम्बूलेंस वाहन, राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश रेड क्रॉस को प्रदान किए गए है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राम नवमी की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राम नवमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व हम सभी को जीवन में अच्छाई के साथ निरन्तर आगे बढ़ने और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कामना की कि यह पर्व प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि हमें मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के संदेशों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने

यह बात कांगड़ा जिला में दिल्ली पब्लिक स्कूल तियारा के आयोजित समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल पहले से ही नाथपा झाकड़ी और मनाली में अंग्रेजी माध्यम सह-शिक्षा प्रदान कर रहा है और यह प्रदेश में उनका तीसरा स्कूल होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 131 स्नातक महाविद्यालय, 1,878 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 931 उच्च विद्यालय, पांच अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, चार फार्मेसी महाविद्यालय 16 पॉलिटेकनिक महाविद्यालय और 138 औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के लिए अनेक बहुआयामी कदम उठाए गए हैं।

इससे पूर्व, वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि इस तरह के संस्थान न केवल स्थानीय शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सांसद किशन कपूर, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, एसपी खुशाल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

मण्डी बस हादसे की प्रारम्भिक रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण मानवीय भूल बताया:परिवहन मंत्री

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल, 2022 को हुए मण्डी बस हादसे की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण मानवीय भूल बताया गया है, परन्तु इस दुर्घटना की सघन जांच के लिए जिला दण्डाधिकारी, मण्डी को निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मण्डी बस हादसे में दुर्घटनाग्रस्त बस की 2 अप्रैल, 2022 को कार्यशाला में चालक द्वारा दिए गए प्रत्येक दोष की मुरम्मत की गई थी तथा 3 अप्रैल को यह बस शिमला-मनाली रूट पर तैनात की गई थी। कार्यशाला में चालक द्वारा दिए गए दोषों की मुरम्मत के लिए प्रत्येक कलपुर्जा भंडार में उपलब्ध था।

परिवहन मंत्री ने कहा कि चम्बा में हुआ बस हादसा बैटरी की तारों में ईंधन आपूर्ति पाइप के पास शोर्ट सर्किट होने के कारण हुआ है। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि मण्डी बस दुर्घटना में मृतकों व घायलों को तुरंत अंतरिम राहत प्रदान की गई। परिवहन निगम द्वारा मृतक चालक के परिवार और मृतक व्यक्ति (यात्री) के परिवार को 25-25 हजार रुपये एवं अन्य घायलों को 1.31 लाख रुपये की फौरी राहत दी गई।

परिवहन निगम द्वारा घायल यात्रियों के उपचार का पूर्ण व्यय वहन किया जा रहा है तथा निगम की नीति के तहत मृतक चालक की पत्नी को तुरंत नौकरी देने का प्रावधान किया जा रहा है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि संयुक्त समन्वय मोर्चा द्वारा परिवहन निगम पर लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। वर्तमान में परिवहन निगम के पास कलपुर्जो और बसों की मुरम्मत के लिए यान्त्रिकों की कोई कमी नहीं है। निगम द्वारा हाल ही में वर्कशोप के पीस मील कर्मियों को अनुबन्ध पर लाया गया है, जिससे बसों के रख-रखाव में बढोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि निगम द्वारा कलपुर्जो की खरीद केवल वाहन निर्माता कम्पनियों से ही की जाती है खुले बाजार से नहीं। उन्होंने कहा कि संयुक्त समन्वय मोर्चा के गैर जिम्मेदाराना ब्यान से यात्रियों व स्टाफ के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम प्रदेशवासियों को सुखद व गुणात्मक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी समयबद्ध रूप से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प: जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी जिला के सुन्दरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी में आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अन्तर्गत विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन-वी केयर (दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य पर्व) का शुभारंभ किया। उन्होंने विशेष ओलम्पिक के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया तथा विशेष ओलम्पिक

संघ को 25 लाख रूपये अनुदान राशि देने की घोषणा की।

इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले चार वर्षो में इस वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने व उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए खेल क्षेत्र में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन व बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में विशेष ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 75 हजार रूपये, रजत पदक विजेता को 50 हजार रूपये, कांस्य पदक विजेता को 20 हजार रूपये तथा अन्य प्रतिभागियों को 10 हजार रूपये की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है।

शिक्षा को व्यक्ति के समग्र विकास का मूल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पहली कक्षा से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों सहित विश्वविद्यालय स्तर तक दिव्यांग बच्चों से ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है तथा उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। दिव्यांग छात्रों को पहली कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने में बिना किसी आय सीमा के 625 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक प्रति माह की दर से छात्रवृति प्रदान की जा रही है। परिणामस्वरूप दिव्यांगजन उच्च शिक्षा प्राप्त करके जीवन में विशेष सफलताएं अर्जित कर हर क्षेत्र में पारंगत व आत्मनिर्भर हुए हैं और शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मूक-बधिर व दृष्टि-बाधित बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सुन्दरनगर व ढली में 12वीं कक्षा तक विशेष योग्यता संस्थान संचालित करके उन्हें नि:शुल्क शिक्षा व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं में सम्मिलित करने के उद्देश्य से डिजिटल व देश में मान्य यूनिक नम्बर दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को गरिमापूर्ण व स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए लिए देशव्यापी सुगम्य भारत अभियान आरंभ किया गया है, जिसके तहत देश में सैंकड़ों भवन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में कई सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। वर्ष 2019 में आबूधाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक खेलों में हिमाचल प्रदेश के विशेष रूप से सक्षम प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 12 पदक जीत कर प्रदेश को गौरवान्वित किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्पेशल ओलम्पिक भारत में विश्व, शरद एवं ग्रीष्म खेलों के विजेता सहयोग स्पेशल स्कूल सुन्दरनगर के जगदीश को स्नो गोल्ड में दो कांस्य पदक, शुभम सिंह को एल्पाईन स्कीइंग में दो रजत पदक, चिराग ठाकुर को बास्केटबॉल में रजत पदक, राहुल को फुटबॉल में पांचवें स्थान पर रहने तथा पार्थ मल्होत्रा को स्नो शूईग में भाग लेने के लिए पुरस्कृत किया ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने इस मौके पर कहा कि ''आजादी का अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम में विशेष ओलम्पिक को जोड़ना दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान दर्शाता है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 75 शहरों में 7500 चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से 75000 दिव्यांग जनों की स्वास्थ्य जांच करके लाभान्वित किया जा रहा है और इस कीर्तिमान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जायेगा। वेदों का कथन है कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं हो सकता अगर उसकी क्षमता को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए और संघ द्वारा इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है।

सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने क्षेत्र में दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी।

स्पेशल ओलम्पिक संघ भारत के हिमाचल चैप्टर की उपाध्यक्ष रशिम धर सूद ने संघ की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

बाल विकास परिषद की महासचिव पायल वैद्य ने दिव्यांगजनों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने के दृष्टिगत इस कार्यक्रम को सराहनीय बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुन्दरनगर सहित तीन शिविरों का आयोजन करके एक हजार दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने, जागरूक करने तथा स्वास्थ्य जांच के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया ।

कांगड़ा चाय को शीघ्र यूरोपीय संघ का जीआई टैग मिलने की सम्भावना

शिमला/शैल। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सभी सम्बद्ध विभागों के सामूहिक प्रयासों से कांगड़ा चाय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है और शीघ्र ही कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ के जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक) मिलने की सम्भावना है।

उन्होंने कहा कि चाय की खेती और विकास का विषय अप्रैल 1999 में उद्योग विभाग से कृषि विभाग को स्थानांतरित किया गया था। इसके उपरान्त प्रदेश में और विशेष तौर पर कांगड़ा चाय की खेती में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विभाग के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में कांगड़ा चाय को भारत में जीआई टैग मिला था।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में चार विभागों-टी बोर्ड ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पालमपुर, राज्य के सहकारी और कृषि विभाग, सीएसआईआर-आईएचबीटी पालमपुर और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चाय उत्पादकों को एक लाख से अधिक पौधे प्रदान किए गए और 5.6 हेक्टेयर नए क्षेत्र में चाय की पौध लगाई गई है। विभाग चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को दो रुपये प्रति पौध तथा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को एक रुपये प्रति पौधा उनके घर-द्वार पर उपलब्ध करवा रहा है।

विभाग भारतीय टी बोर्ड और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के चाय विभाग के वैज्ञानिकों के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की जा रही नई तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान कर चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। 14 दिसम्बर, 2021 को आईएचबीटी पालमपुर द्वारा टी फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े चाय बागानों, छोटे उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों व चाय उत्पादकों ने भाग लिया।

सौर ऊर्जा संयंत्रों पर उपदान चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति किलोवाट किया

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थानों के भवनों की छत पर स्थापित किए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर देय राज्य उपदान में बढ़ोतरी कर इसे 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है। उपदान की राशि भारत सरकार द्वारा दिए गए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगी। उपदान की राशि हिमऊर्जा के माध्यम से सीधे तौर पर सम्बन्धित उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता इसे बनाना पड़ता है जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है।
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

महंगाई के साथ उठते सवाल

महंगाई पर संसद में बहस नहीं हो सकी है क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। बल्कि संसद के बाहर सत्तारूढ़ भाजपा महंगाई को जायज ठहराने के लिये दूसरे देशों के तर्क दे रही है। लेकिन श्रीलंका का नाम लेने से परहेज कर रही है। आरबीआई ने भी यह मान लिया है कि अभी महंगाई कम नहीं हो सकती। इस महंगाई के कारण विकास दर भी अनुमानों से कम रहेगी यह भी आरबीआई ने स्वीकार लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ मामलों पर सुनवाई करते हुये सरकारों को सलाह दी है कि वह योजनायें बनाते समय वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। चुनाव आयोग ने सरकारों द्वारा घोषित मुफ्त उपहारों की योजनाओं पर कहा है कि इन्हें रोकने की उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। ऐसी मुफ्त योजनाओं पर फैसला जनता को ही लेना होगा यह चुनाव आयोग की सलाह है। प्रधानमंत्री के साथ पिछले दिनों भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की हुई एक बैठक में मुफ्ती योजनाओं पर बात उठाते हुये कुछ अधिकारियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इन्हें न रोका गया तो हमारे भी कई राज्यों की हालत श्रीलंका जैसी हो जायेगी। मुफ्ती योजनाओं पर इन अधिकारियों का संकेत आम आदमी पार्टी की ओर था। प्रधानमंत्री के साथ अधिकारियों की यह बैठक काफी वायरल हो चुकी है।

आम आदमी पार्टी ने जिस तर्ज पर दिल्ली में मुफ्ती योजनाओं को अंजाम दिया है उसके परिणाम स्वरूप उसने दो बार भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा है। इसी मुफ्ती के नाम पर उसने पंजाब में दोनों दलों से सत्ता छीन ली है। अन्य राज्यों में भी वह इसी प्रयोग को दोहराने की योजना पर चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संदेश एक ऐसा नारा है जो हर वर्ग के हर आदमी को सीधे प्रभावित करता है। यही दोनों क्षेत्र इस शासनकाल में सबसे बड़े व्यवसायिक मंच बन गये हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक की सभी सरकारें इस व्यपारिकता को रोकने की बजाये आप की तर्ज पर मुफ्ती के चक्रव्यूह में उलझ गयी है। इसलिये निकट भविष्य में इस मुफ्ती के जाल से कोई भी राजनीतिक दल बाहर निकल पायेगा ऐसा नहीं लगता। एक और मुफ्ती का बढ़ता प्रलोभन और दूसरी ओर हर क्षेत्र प्राइवेट सैक्टर के लिये खोल देना समाज और व्यवस्था के लिये एक ऐसा कैंसर सिद्ध होंगे जिस के प्रकोप से बचना आसान नहीं होगा।

ऐसे में यह सवाल अपने आप एक बड़ा आकार लेकर यक्ष प्रशन बनकर जवाब मांगेगा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। क्योंकि मुफ्ती की भार उठाने के लिये हर वर्ग पर परोक्ष /अपरोक्ष करों का बोझ डालना पड़ेगा। करों से सिर्फ कर्ज लेकर ही बचा जा सकता है। क्योंकि हर वह क्षेत्र जिससे राष्ट्रीय कोष को आय हो सकती थी वह प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर दिया गया है। इसलिये तो जून 2014 में देश का जो कर्ज भार 54 लाख करोड़ था वह आज बढ़कर 130 लाख करोड़ हो गया है। आईएमएफ के मुताबिक यह कर्ज इस वर्ष की जीडीपी का 90% हो जायेगा। यह आशंका बनी हुई है कि हमारी कई परिसंपत्तियों पर विदेशी ऋणदाता कब्जा करने के कगार पर पहुंच गये हैं। राजनीतिक दलों की प्राथमिकता येन केन प्रकारेण सत्ता पर कब्जा करना और फिर उसे बनाये रखना ही हो गया है। दुर्भाग्य यह है कि संवैधानिक संस्थान भी इस दौड़ में दलों के कार्यकर्ता होकर रह गये हैं। जनता को हर चुनाव में नए नारे के साथ ठगा जा रहा है। मीडिया अपनी भूमिका भूल चुका है क्योंकि बड़े मीडिया संस्थानों पर सत्ता के दलालों का कब्जा हो चुका है। छोटे मीडिया मंचों का गला सत्ता घोंटने में लगी हुई है। इसी सब का परिणाम है कि जिस बड़े शब्द घोष के साथ नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाने का दावा किया था उसी अनुपात में यह कब्जा पांच राज्यों के चुनाव में और पूख्ता हो गया हैं। इस वस्तु स्थिति से निकलने के लिये चुनावी व्यवस्था को बदलना ही एकमात्र उपाय रह गया है । इस पर अगले अंक में चर्चा बढ़ाई जाएगी।

इन-ट्रांस एई-II कार्यक्रम के तहत भारतीय यातायात परिदृश्य के लिये स्वदेशी आईटीएस सॉल्यूशंस

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन सिटीज फेज-II के लिये इंटेलीजेंट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम्स (आईटीएस) (कुशल यातायात प्रणाली) के तहत स्वदेशी ऑनबोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम (ओडीएडब्लूएस), बस सिग्नल सिस्टम तथा कॉमन स्मार्ट आई-ओटी कनेक्टिव (कॉस्मिक) साफ्टवेयर का शुभारंभ कर दिया गया है। इस उत्पाद को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार ने जारी किया।

इस अवसर पर मंत्रालय के जीसी (इलेक्ट्रॉनिक आर-एंड-डी) अरविन्द कुमार, अमेरिका के पडयर्डू यूनिवर्सिटी के डॉ. सतीश वी. उक्कूसूरी, इन-ट्रांस एसई कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो. एचपी किन्चा, ईएसओडी की विभागाध्यक्ष और साइंटिस्ट-'जी' सुनीता वर्मा तथा मंत्रालय के साइंटिस्ट 'डी' कमलेश कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस उत्पाद को प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडैक) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी-एम) की संयुक्त पहल के जरिये विकसित किया गया है। महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने परियोजना के लिये औद्योगिक सहयोग दिया।

1. ऑनबोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम - ओडीएडब्लूएस: विकसित राजमार्ग अवसंरचना और वाहनों की अधिकता के साथ-साथ सड़कों पर गति में इजाफा हुआ है, जिसके कारण सुरक्षा की चिंता भी बढ़ गई है। केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार दुर्घटना के लगभग 84 प्रतिशत मामले 'चालक की गलती' से होते हैं। इसलिये वाहन चालन में गलतियां न्यूनतम करने के लिये चालकों की सहायता तथा चेतावनी के सम्बंध में सक्षम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

ओडीएडब्लूएस में चालक के नजदीक आने की निगरानी के लिये वाहन-आधारित सेंसर लगाने का प्रावधान है। साथ ही चालक की सहायता के लिये वाहन के आसपास सुनने और नजर आने वाले अलर्ट भी इसमें शामिल हैं। परियोजना में नौवहन इकाई, चालक सहायता केंद्र और एमएम-वेव रडार सेंसर जैसे उपायों का विकास किया जा रहा है। आसपास के वाहनों की स्थिति और उनकी दशा के बारे में जानने के लिये एमएम-सेंसर का इस्तेमाल होता है। नौवहन सेंसर से वाहन की सटीक जियो-स्पेशल स्थिति पता चलेगी। साथ ही वाहन किस तरह चलाया जा रहा है, इसके बारे में भी पता चलेगा। ओडीएडब्लूएस एलॉगरिद्म को सेंसर के डेटा को समझने में इस्तेमाल किया जाता है और इनसे वाहन चालक को वास्तविक समय में सूचना दी जाती है, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ जाती है।

2. बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम: सार्वजनिक यातायात प्रणाली का कम भरोसेमंद होने के कारण लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग सार्वजनिक यातायात के प्रति आकर्षित हों। इस तरह ज्यादा वहनीय यातायात समाधान होगा। शहरी इलाकों में सार्वजनिक बसों के विलंब का प्रमुख कारण सिग्नल वाले अति व्यस्त चौराहे होते हैं।

बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम परिचालन रणनीति है, जो सामान्य यातायात सिग्नल संचालन को बेहतर बनाने के लिये है, ताकि सार्वजनिक वाहनों को सिग्नल द्वारा नियंत्रित चौराहों पर आराम से निकाला जा सके। आपातकालीन वाहनों के लिये तुरंत प्राथमिकता के विपरीत, यहां शर्त आधारित प्राथमिकता दी जाती है। यह तभी दी जाती है, जब सभी वाहनों के लिये विलंब में कटौती हो रही हो। यह विकसित प्रणाली सार्वजनिक बसों को प्राथमिकता देकर अन्य वाहनों के विलंब में कमी लायेगी। इसके लिये हरी बत्ती के अंतराल को बढ़ाया जायेगा और लाल बत्ती के अंतराल को कम किया जायेगा। यह प्रणाली उस समय काम करना शुरू कर देगी, जब किसी चौराहे पर वाहन पहुंच रहे होंगे।

3. कॉमन स्मार्ट आई-ओटी कनेक्टिव (कॉस्मिक): यह मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है, जो वन-एम2एम आधारित वैश्विक मानक का पालन करते हुये आईओटी की तैनाती करता है। इससे उपयोगकर्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचार के मामले में मुक्त इंटरफेस प्रदान करता है। ये सभी सेवा प्रदाता वन-एम2एम मानक का पालन करते हैं। इसे ध्यान में रखकर कॉस्मिक सामान्य सेवा को किसी भी विक्रेता के इंटरफेस के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके विशिष्ट मानक हैं। इसका इस्तेमाल स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड के संचालन को बढ़ाकर किये जाने के लिये है।

एक निश्चित केंद्र पर आधारित यह परिचालन व्यवस्था और आंकड़ों का आदान-प्रदान आईओटी उपकरणों तथा एप्लीकेशनों के बीच होता है, ताकि वेंडर लॉक-इन को टाला जा सके। कॉस्मिक में 12 सामान्य सेवायें शामिल हैं -पंजीकरण, खोज, सुरक्षा, सामूहिक प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, डेटा प्रबंधन एवं भंडारण, सब्सक्रिप्शन एवं सूचना, उपकरण प्रबंधन, एप्लीकेशन एवं सेवा प्रबंधन, संचार प्रबंधन, आपूर्ति, नेटवर्क सेवा, लोकेशन, सेवा शुल्क और लेखा परीक्षण।

कॉस्मिक प्लेटफॉर्म से कनेक्टिंग गैर-वन-एम2एम (नो-डीएन) उपकरण या तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन के लिये इंटरवर्किंग प्रॉक्सी एंटिटी (आईपीई) आपीआई मिलता है, ताकि वे कॉस्मिक प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। कॉस्मिक एक डैशबोर्ड पेज भी मुहैया कराता है, जहां आईओटी इकाइयों, उत्पादों, एप्लीकेशनों और जियोग्राफीकल इंफर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) मानचित्र में प्रत्यक्ष डेटा दिखता है। चार्टों और रिपोर्टों के लिये दूसरे क्रम के आंकड़े भी उपलब्ध हैं। कॉस्मिक में आईओटी उपकरणों तथा एप्लीकेशनों के निर्बाध संपर्क के लिये आमूल समाधान भी मिलता है।

सहकार से समृद्धि–भारत के विकास की कुंजी

– आर एस सोढ़ी –
प्रबंध निदेशक
जीसीएमएमएफ लिमिटेड (अमूल)

यदि भारत को तेजी से और समानता के साथ विकास करना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा है कि 'भारत' भी 'इंडिया' के साथ कदम मिलाकर विकास के पथ पर आगे बढ़े। 'भारत' व्यापार करने के सहकारी तरीके से भी विकसित हो सकता है, क्योंकि छोटे लोगों का ध्यान रखने वाला यही एकमात्र मॉडल है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर तीन 'S' पर आधारित है जो इस प्रकार हैं–

(क) छोटे किसान, छोटे व्यापारी और छोटे श्रमिक

(ख) छोटे खुदरा विक्रेता और छोटे बिचौलिए

(ग) छोटे उपभोक्ता

'इंडिया' के बढ़ते धन और समृद्धि को 'भारत' के साथ साझा करने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये तीनों 'S' विकास प्रक्रिया में शामिल हों। हमारे नीति–निर्माता यह समझते हैं कि वह बिजनेस मॉडल जो इन तीनों 'S' का सही तरीके से ध्यान रख सकता है, वह व्यवसाय या बिजनेस करने का सहकारी तरीका ही है। सहकारी समितियां शहरी और ग्रामीण भारत के बीच या 'इंडिया' और 'भारत' के बीच बढ़ती आय असमानता को कम करने में मदद कर सकती हैं।

सहकारी मॉडल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के हाशिए पर पड़े तबके को एक साथ लाने और समाज में उनके उत्थान में सहायता करने में अपने महत्व को बार–बार साबित किया है। जनता के स्वामित्व में लोकतांत्रिक रूप से चलने वाली सहकारी समितियां, यह सुनिश्चित करती हैं कि आर्थिक विकास समाज के सभी वर्गों द्वारा समान रूप से साझा हो।

इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'सहकार से समृद्धि' का नारा दिया है। इसका अर्थ है सहयोग के माध्यम से समृद्धि। उन्होंने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया है जिसका नेतृत्व माननीय गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। हमारी सरकार समझती है कि भारत के समावेशी विकास के लिए हमें सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहकारी समितियों की आवश्यकता है क्योंकि सहकारी व्यवसाय मॉडल केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कहीं भी लागू किया जा सकता है।

सहकारी संस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए पिछले केंद्रीय बजट में लगभग 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था। यह सहकारी संस्थाओं और उसकी धारणा पर केंद्र सरकार के विश्वास को दर्शाता है। बजट में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण के लिए 350 करोड़, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बजट, और सहकारी समितियों को परिवर्तित करने में सहयोग के रूप में उनके वित्त, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के लिए अम्ब्रेला योजना (Umbrella Scheme) 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि' के माध्यम से 274 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है।

भारत में सहकारी आंदोलन 117 वर्ष से अधिक पुराना है। इसने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, मछुआरों और कारीगरों को विकास प्रक्रिया में सम्मिलित करने में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस जीवंत सहकारी आंदोलन को हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिसके कारण भारत पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्रेडिट सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों ने बैंकिंग/एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से देश के कई क्षेत्रों में साहूकारों की बेड़ियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय डेयरी क्षेत्र में, ग्रामीण भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों के लिए डेयरी सहकारी समितियों का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि सहकारी समितियों ने उन्हें बाजार तक पहुंच बनाने और अपने उपज तथा उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त करने में अपनी सामूहिक ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। डेयरी सहकारी आंदोलन ने कुछ ही दशकों में भारत को दूध की कमी वाले राष्ट्र से विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बना दिया है। इसने हमारे देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर राष्ट्र निर्माण में अत्यधिक योगदान दिया है। साथ ही, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र– दूध और दूध उत्पादों में हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा की है।

यदि सहकारी मॉडल नहीं होता तो, तो भारत आज अपने पड़ोसी देशों और अन्य एशियाई देशों की भांति डेयरी उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर होता और इसकी कीमत आज भारत में आयात होने वाले सालाना 5–6 लाख करोड़ रुपये के खाद्य तेल के बराबर होती। डेयरी सहकारी समितियों की विशिष्टता यह है कि यह ग्रामीण भारत में 365 दिनों (वर्ष पर्यंत) के लिए रोजगार (विशेष रूप से महिलाओं को) उत्पादकों को खराब होने वाली वस्तुओं के लिए गारंटीकृत बाजार, और पूरे वर्ष नकदी प्रवाह की सुनिश्चितता प्रदान कर रही है जो अंततः महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाती है।

पूरे भारत में डेयरी क्षेत्र सहकारी मॉडल की प्रतिकृति ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी व्यय से बचाया है बल्कि कुल आय का 75–80% उत्पादकों को दिलाने में भी सफल रहा है। केवल कुछ वर्षों के लिए ही नहीं, बल्कि विगत कई दशकों से भारत की डेयरी सहकारी समितियों ने यह सुनिश्चित किया है कि दूध उत्पादक सदस्य, जिनके पास पूरी आपूर्ति श्रृंखला है, उन्हें उपभाक्ता से प्राप्त होने वाले रुपये का कम से कम 75–80% वापस मिले जो डेयरी क्षेत्र में विकासशील देशों में बहुत कम है जहाँ दूध उत्पादक उपभोक्ता रुपये का लगभग 30–35% ही प्राप्त कर पाता है।

व्यवसाय में सहकारी मॉडल अपनाने के प्रमुख लाभों में शामिल हैं– बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, किफायती लागत, अंतिम उपभोक्ता के लिए सस्ती पेशकश, नई प्रौद्योगिकियों के लिए तेजी से अनुकूलन, वित्त तक बेहतर पहुंच और वितरण सुविधाओं का तेजी से विस्तार सम्मिलित है। 'भारत' और 'इंडिया' के बीच धन का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें काम करने की नियंत्रणात्मक शैली से अधिक विकासात्मक भूमिका की ओर बढ़ें, सहकारी समितियों को अधिक आधुनिक और समकालीन बनाने में मदद करें तथा शहरी भारत में सहकारी व्यवसाय म डल का अनुकरण करें।

वस्तुतः समाज और अर्थव्यवस्था कोई भी हो, सहकारिता अपने सदस्यों और संभावित ग्राहकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सहकारी संरचना किसी भी स्थिति में सबसे अच्छा काम करती है जहां व्यक्तिगत उद्यमी कमजोर होता है, लेकिन यह प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ बड़ी संख्या में सदस्यों को गठबंधन की सामूहिक ताकत से लाभान्वित करने में सक्षम बनाती है। सामूहिक गठबंधन समाज के भीतर जरूरतों और समस्याओं को हल करते हुए व्यक्तिगत सदस्य को बाजार पहुंच, वित्तीय पहुंच और लाभकारी आजीविका प्राप्त करने में मदद करता है।

आसान पूंजी के प्रावधान, पेशेवरों को आकर्षित करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता किसी भी नई सहकारी समिति के गठन के लिए मुख्य चुनौतियां होती हैं। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक नवगठित सहकारी समितियों को चलाने, मार्गदर्शन करने और विस्तार करने के लिए निस्वार्थ और समर्पित नेतृत्व की आवश्यकता है। आज के राजनीतिक नेतृत्व को पहले से ही सफल सहकारी समितियों से आगे बढ़ने और नए क्षेत्र या नवगठित सहकारी संस्था के पोषण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

'सहकार से समृद्धि' जमीनी स्तर पर, (क) स्थानीय उद्यमशीलता कौशल की सामूहिक ताकत का उपयोग द्वारा, (ख) तेजी से और समान आर्थिक विकास द्वारा, (ग) आत्म–निर्भर भारत की दृष्टि को तेजी से प्राप्त करने के द्वारा तथा (घ) 'वोकल फार लोकल' के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन द्वारा लोगों पर आधारित विकासात्मक प्रयासों को आसान बना सकती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था नए व्यवसायों और स्टार्टअप की लहर अनुभव कर रही है। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उभरते व्यवसाय छोटे उत्पादकों या सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले एकत्रीकरण या सहकार के मॉडल पर आधारित हैं और लागत प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। जोमैटो, उबर और अमेजन जैसे यूनिकॉर्न ने एकत्रीकरण या सहकार की क्षमता का उपयोग करके अपने व्यवसाय का निर्माण किया है। सामान्य धारणा के विपरीत, एक सहकारी व्यवसाय मॉडल केवल डेयरी, ऋण या आवास क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनाया जा सकता है, जहां छोटे उत्पादक या सेवा प्रदाता, छोटे बिचौलिए और छोटे उपभोक्ता शामिल होते हैं। खाद्य वितरण, सुरक्षा और मजदूर, हाउसमेड सेवाएं, टैक्सी आदि जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन करना भी संभव और जरूरी है।

'सहकार से समृद्धि' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो ग्रामीण समृद्धि में सुधार करेगा और असमानता को कम करेगा। साथ ही, यह 'आत्मनिर्भर भारत' को एक वास्तविक बनाएगा। यह भारत में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने के साथ–साथ धन के समान वितरण को बढ़ावा देता है। सहकारिता 'इंडिया' और 'भारत' दोनों के आर्थिक विकास के लिए एक साधन है और यह भारतीय लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भी काम करेगा।

चिंतपूर्णी मंदिर के योजनाबद्ध विकास में कारगर साबित होगी प्रसाद योजना

शिमला। पर्यटन को बढ़ावा देने में विरासत स्थल और धार्मिक पर्यटन का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। इनका एकीकृत विकास जहां पर्यटन की आधारभूत संरचना को सुदृढ करता है वहीं यह रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने में भी सहायक है। इस दिशा में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई प्रसाद योजना (तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक आवर्द्धन अभियान योजना) ऊना जिला स्थित माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर परिसर के सतत् एवं योजनाबद्ध विकास में कारगर साबित होगी।

प्रसाद योजना महत्वपूर्ण तीर्थ एवं विरासत स्थलों के समावेशी, एकीकृत व बुनियादी ढांचे के विकास के साथ आजीविका, कौशल, स्वच्छता, सुरक्षा, पहुंच और सेवा वितरण पर केन्द्रित है।

प्रसाद योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुविधाओं के विस्तार पर 40.07 करोड़ रुपये व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। मां चिंतपूर्णी मंदिर में इस योजना को लागू करने के लिए 1696 वर्गमीटर क्षेत्र की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 1039 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया है, यानी 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और शेष लक्ष्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

मां चिंतपूर्णी मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि प्रसाद योजना के लागू होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। अधिक श्रद्धालु आएंगे, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रसाद योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर के लिए स्वीकृत किए गए 40.07 करोड़ रुपये में से 26.12 करोड़ रुपये मंदिर परिसर के विस्तार पर व्यय होंगे। मंदिर परिसर में तीन गेट, श्रद्धालु सुविधा केंद्र, रेलिंग, मंदिर की सजावट, ड्रेनेज सिस्टम का सुधार, शीशे की छत्त, तारों को अंडरग्राउंड करना आदि निर्माण कार्य किये जाएंगे। वहीं 5.36 करोड़ रुपये रास्तों के सुधार, वॉटर एटीएम, तीन शैड, सोलर लाईट, कचरा प्रबंधन, ई–टॉयलेट्स के निर्माण के साथ–साथ अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय किए जाएंगे। 6.06 करोड़ रुपये से सीसीटीवी, डिजिटल डिस्पले सिस्टम, प्रतीक्षालयों में एलईडी स्क्रीन तथा बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद पर व्यय होंगे।

प्रसाद योजना के लागू होने के उपरांत श्रद्धालुओं को एक ही छत्त के नीचे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बहुत सी समस्याओं का स्थाई समाधान होगा। मंदिर में भीड़ का प्रबंधन करने की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ होंगी।

मां चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में प्रसाद योजना के कार्यान्वयन से आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश भी होगा।

प्रसाद योजना से धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में धार्मिक स्थलों के विकास एवं इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं सृजित करने के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में प्रदेश में विशिष्ट पहचान वाले 75 गांवों को देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए बड़ी कार्य योजना की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश के इन गांवों व राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व ऐतिहासिक विशिष्टता देश और दुनिया के सामने आ सकेगी।

मुख्यमंत्री ने थुनाग में औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के परिसर का शिलान्यास किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी जिला के थुनाग में लगभग 240 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के परिसर का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 52 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में इस महाविद्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा और इसमें प्रशासनिक खण्ड, पुस्तकालय भवन, खेल मैदान, व्यायामशाला, सभागार, शॉपिंग सेंटर, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रों और छात्राओं के लिए अलग छात्रावास और एक पीजी छात्रावास की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में आठ प्रशासनिक खण्ड होंगे, जिसमें चार औद्यानिकी महाविद्यालय और चार वानिकी महाविद्यालय तथा अन्य सम्बन्धित अधोसंरचना के लिए होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में छात्रों और छात्राओं के लिए दो छात्रावास, एक प्रशासनिक खण्ड और एक शैक्षणिक खण्ड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस महत्वकांक्षी परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह

महाविद्यालय क्षेत्र में बागवानी विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को कुलपति द्वारा कॉफी टेबल बुक भेंट की गई।

डॉ. यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के कुलपति डॉ. परविन्द्र कौशल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि थुनाग में बागवानी और वानिकी महाविद्यालय में 250 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया परिसर प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की माता बृकुमू देवी, निदेशक उद्यान डॉ. आर.के. परुथी, मंडी के उपायुक्त अरिन्दम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री करेंगे चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर 15 अप्रैल, 2022 को चम्बा जिला मुख्यालय स्थित चौगान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और वन मंत्री राकेश पठानिया भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे।

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर मण्डी में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी जिला कांगड़ा के धर्मशाला में, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा जिला लाहौल-स्पीति के केलांग में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ऊना में, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह हमीरपुर में, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर कुल्लू में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल सोलन में, ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी जिला सिरमौर के नाहन में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग बिलासपुर में और विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अधयक्षता करेंगे।

मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग केंद्र परौर का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के परौर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक गुरू बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लों के सत्संग में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास आध्यात्म, समाज सेवा, मानवता, भाईचारे और ईमानदारी

के प्रसार में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने आध्यात्म को सदैव अपना प्रमुख मूल्य मानते हुए सहजता को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा परौर केंद्र को समर्पित कोविड केयर सेन्टर बनाने के कार्य में हर सम्भव सहायता प्रदान करने की सराहना की।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध चामुण्डा मन्दिर में पूजा-अर्चना की तथा कंजक पूजन और यज्ञ में भाग लिया।

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी, सांसद किशन कपूर, विधायक अरूण कुमार, वूलफेडशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा, राज्य संयोजक भाजपा पर्यटन प्रकोष्ठ विनय शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्र भूषण नाग, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा, मीडिया समन्वयक विश्व चक्षु और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की जयपुर में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रज्ञी गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हिमाचल का प्रतिनिधित्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर सिंह ने किया, जिसमें उन्होंने हिमाचल में विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यो पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल जल शक्ति विभाग ने अनेक मील पत्थर स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा 95 प्रतिशत घरों में नल लगाए गए हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहौल-स्पीति के सभी घरों में तथा सुखग्रस्त ऊना व चम्बा में हर घर में नल लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि नलों की कार्यशीलता तथा जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में भी केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत 7030 युवाओं

को प्रशिक्षित किया गया।

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रदेश में कुल 60 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से 50 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परिक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रति प्रयोगशाला प्रशिक्षण में भी हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिमाचल जल जीवन मिशन के कार्यो और हिमाचल प्रदेश को दी गई प्रोत्साहन राशि पर सराहना करते हुए अन्य राज्यों को हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पर्वतीय राज्य से सीखने की सलाह दी है। कार्यशाला में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता संजीव कौल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता जल मिशन के निदेशक जोगेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित थे।

90 दिनों में दायर हो कोविड से होने वाली मृत्यु का दावा:सुप्रीम कोर्ट

शिमला/शैल। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 539 में, विविध आवेदन संख्या 1805, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के कारण मृतक जनों के परिवारों को यथा घोषित कोविड-19 के कारण मृतक जनों के परिवारों को दावा दायर करने हेतु लाभार्थियों के लिए अपने आदेश दिनांक 24 मार्च, 2022 के द्वारा निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की है।

न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 20 मार्च, 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च, 2022 से साठ दिनों की बाह्य समय सीमा लागू होगी।

भविष्य में कोविड-19 से होने वाली किसी भी मृत्यु के लिए दावा दायर करने के लिए समय-सीमा मृत्यु की तिथि से नब्बे दिन की होगी।

दावों की जांच एवं कार्यवाही करने के लिए दावे की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने का पूर्व आदेश जारी रहेगा।

हालांकि न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर सकता है तो वह दावेदार शिकायत निवारण समिति के माध्यम से ऐसा कर सकता है। ऐसे दावों पर शिकायत निवारण समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा और अगर शिकायत निवारण समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार उस निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है तो उस मामले में दावे पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि फर्जी दावों के जोखिम को कम से कम करने के लिए 5 प्रतिशत दावा आवेदनों की पहली बार में रैन्डेम जांच की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी दावा किया है, तो उस पर डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत विचार किया जाएगा और तदनुसार उसे दंडित किया जा सकता है।

दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अन्तर्गत सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुले और बंद होने के समय तय कर दिया है।

उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय प्रात: नौ बजे तथा बंद होने का समय रात्रि आठ बजे रखा गया है।

शिमला और धर्मशाला नगर निगमों और मनाली नगर परिषद में दुकानें प्रात: नौ बजे खोली जाएंगी और रात्रि 9.30 बजे बंद की जाएंगी।

प्राकृतिक खेती राज्य की ओर हिमाचल

प्राकृतिक खेती किसानः 1,71,063

भूमिः 1,17, 762 बीघा (23,552 एकड़)

पंचायतेंः 3,590 (99.3%)

रसायनमुक्त, पोषणयुक्त तथा स्थानीय उत्पाद अपने आस-पास के प्राकृतिक खेती कर रहे किसान से ही खरीदें।

अधिक जानकारी हेतू

अपने ब्लॉक में कृषि विभाग के खंड तकनीकी प्रबंधक (BTM) या सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM) से संपर्क करें।

जारीकर्ताः राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, कृषि भवन, शिमला-5 | spnf-hp@gov.in /spnfhp.nic.in /spnfhp /spnfhp /spnfhp 0177-2830767

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्सः 2805015

धूमल की याचिका पर नड्डा के फैसले से गरमाई भाजपा की राजनीति

शिमला/शैल। प्रदेश के आने वाले चुनाव जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में लड़े जायेंगे और मंत्री परिषद में भी कोई बदलाव नहीं होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के इस स्पष्ट ब्यान से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गयी है। क्योंकि नड्डा स्वयं हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और 2017 में धूमल की हार के बाद वह स्वयं भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में आ गये थे। प्रदेश में वह स्वास्थ्य और वन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में क्यों जाना पड़ा था यह राजनीति के जानकार जानते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह ब्यान ऐसे समय में आया है जब आप प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और केजरीवाल ने मण्डी में रोड शो करके चुनाव में हुंकार भरी। मंडी का रोड शो उस दिन था जब भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही थी। इस दिन प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी था। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के नेताओं तक हर कार्यकर्ता और नेता इस आयोजन में व्यस्त था। मुख्यमंत्री स्वयं सराज में थे। इस सबके होते हुये भी जितनी भीड़ केजरीवाल के रोड शो में हो गयी थी वह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए पर्याप्त चुनौती हो जाती है। भाजपा पर इस रोड शो का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना पढ़ा है कि उसी दिन केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर आप के संयोजक और अन्य नेताओं को आप से निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा देते हैं। नड्डा भी रात को ही अपने आवास पर आप के नेताओं को भाजपा में शामिल करने की सारी प्रक्रिया पूरी करके इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सुबह सारे चैनलों की यह बड़ी खबर हो जाती है।

आप में सेंध लगाने के इस प्रोग्राम को दिल्ली में अंजाम दिया जाता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री पर कोई बड़े सवाल न उठे इसलिए नड्डा ने स्वयं और अनुराग को जयराम का दिल्ली में वकील बताकर चर्चा को विराम दे दिया है। लेकिन वह यह भूल गये हैं कि जनता यह जानती है कि वकील तो मोटी फीस लेकर मुकद्दमा लड़ते हैं और यह कतई नहीं होता कि मुकद्दमे के बारे में भी उनकी राय वही हो। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अदालत में याचिकाकर्ता तो प्रेम कुमार धूमल थे। उन्होंने मांग की थी कि धामी की तर्ज पर उनकी हार के कारणों की भी जांच की जाये। नड्डा ने इस मामले पर कोई भी कारवाई डालने की बजाये यह कहकर ही सारे प्रकरण को खारिज कर दिया कि पार्टी गुण दोष के आधार पर फैसला लेती है। अब नड्डा के इस एकतरफा फैसले से यह प्रकरण स्वत: ही जनता की अदालत का विषय बन गया है। जनता ने उप चुनावों के दौरान भी चार शुन्य का परिणाम देकर अपने तेवरों से परिचित करवा दिया है।

अब नड्डा के फैसले के बाद वह भी आने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों के स्वत: भागीदार हो जायेंगे। क्योंकि उपचुनावों के बाद भी महंगाई को कारण बता कर हार की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया गया था। अब पांच राज्यों के चुनावों के बाद फिर महंगाई का उपहार जनता को मिला है। जनता को यह समझ आ चुका है कि चुनावों से पहले महंगाई पर रोक लगायी जायेगी और बाद में उससे दोगुना करके बढ़ाया जायेगा। ऐसे में यह तय है कि चुनावों में सरकार के हर फैसले पर खुलकर चर्चा होगी। क्योंकि जब नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होगा तो हर सवाल का जवाब इसी नेतृत्व को देना होगा। कर्ज के बढ़ते आंकड़े से लेकर कैग रिपोर्ट में उठे सवालों का जवाब इन्हें ही देना होगा। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को यह अभयदान देकर एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। अनुराग ठाकुर ने आप में सेंध लगाकर अपनी राजनीतिक कुशलता और चुनाव सर्वेक्षणों में आ रहे आकलनों पर अपरोक्ष में मोहर लगा दी है। अभी नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं वैसे तो दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी फैसला लेकर चुनावों से बचने का दाव चल सकती है। लेकिन नड्डा के रोड शो में जिस तरह से शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज को हाशिये पर रखा गया है उससे भी कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि पिछले दिनों सुरेश भारद्वाज की केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें रही हैं उससे उन्हें भी नेतृत्व के दावेदारों में गिना जाने लगा था। ऐसे में नड्डा के ब्यान से भाजपा के अंदर भी चर्चाओं का दौर चल पड़ा है।

अनुराग की सेंध ने आप की कार्यशैली पर उठाये सवाल

प्रदेश इकाई भंग करने तक पहुंच गये हालात

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीतने के बाद जिस तर्ज पर हिमाचल और गुजरात में चुनावी हुंकार भरी थी उसमें हिमाचल के हमीरपुर से सांसद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सूई चूभाकर उसकी हवा निकाली है। उससे देश भर में आप की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि मण्डी में केजरीवाल के सफल रोड शो के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह ब्यान आ गया कि भाजपा हिमाचल में जयराम की जगह अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बना रही है। सिसोदिया के इस ब्यान से प्रदेश भाजपा के अन्दर हड़कंप मचना ही था। एकदम इस ब्यान पर जयराम और प्रेम कुमार धूमल की प्रतिक्रियाएं आ गयी। अनुराग ठाकुर ने आप के प्रदेश संयोजक और संगठन मंत्री तथा ऊना के जिला अध्यक्ष को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा कर आप को स्पष्टीकरण जारी करने पर व्यस्त कर दिया। क्योंकि यह कड़वा सच है कि मण्डी के रोड शो में केजरीवाल ने हिमाचल के किसी भी छोटे बड़े नेता को मंच पर जगह नहीं दी और न ही प्रदेश के नेताओं से कोई बैठक की। इसके कारण चाहे जो भी रहे हो उससे आप की व्यवहारिक स्थिति बहाल नहीं हो जाती है। यह सही है कि जयराम के नेतृत्व में भाजपा ने चारों उप चुनाव हारे हैं। अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो तीन ओपीनियन पोल आये हैं उनमें भी भाजपा की जीत नहीं बतायी गयी है। हां यह जरूर कहा गया है कि यदि अनुराग के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। विपक्ष के नजरिये से चाहे वह कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी दोनों को जयराम के मुख्यमंत्री बने रहने से लाभ मिलता है। इस सामान्य सी राजनीतिक सूझबुझ के स्थान पर यदि सिसोदिया जैसा व्यक्ति भाजपा के अंदर के फैसले को इस तरह से ब्रेक करता है तो उससे विपक्ष की बजाये सीधे जयराम को लाभ मिलता है। इसलिए आप में सेन्ध लगाने के ऑपरेशन से जयराम को बाहर रखने के बावजूद नड्डा को जयराम को अभय दान देना पड़ा। सिसोदिया की इस चाल से जहां जय राम को अनचाहे ही राहत मिल गयी है वहीं पर आप की कठिनाई बढ़ जाती है। क्योंकि आप को अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक साथ चुनौती देने की क्षमता रखता हो और साथ ही आम आदमी भी हो। क्योंकि इस समय

हिमाचल भाजपा कांग्रेस और आप तीनों के लिये संवेदनशील प्रदेश बन गया है। भाजपा या कांग्रेस जो भी या दोनों ही प्रदेश हारते हैं तो वह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल पूरे क्षेत्र से बाहर हो जायेगा। यदि आप का हिमाचल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो सबसे पहले उसके दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जायेंगे। साथ ही उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने में और इंतजार करना पड़ेगा।

अनूप केसरी के भाजपा में शामिल होने पर जो प्रतिक्रियाएं आप की ओर से आयी हैं कि वह केसरी की निष्कासित करने जा रहे थे वह अपने में ही बहुत हल्की हैं। क्योंकि आप की अदालत में पेश होकर केजरीवाल ने यह कहा है कि वह आप में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की पूरी जांच करते हैं और तभी उसे कोई जिम्मेदारी देते हैं। अनूप केसरी के मामले में यह विरोधाभास आप को अनचाहे ही कमजोर कर देता है। आप में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहली निष्ठा आर एस एस के प्रति है। बल्कि आर एस एस की अनुमति से आप में शामिल हुये हैं और जिम्मेदारी लेकर बैठें हैं। जबकि आप में वह लोग आज भी बिना किसी पद के बैठे पूरी निष्ठा के साथ संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं जो 2014 में शामिल हुये थे। 2014 में शिमला से सुभाष चंद्र ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय चारों सीटों पर आप लड़ी थी। इसमें शिमला में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सुभाष आज भी बिना पद के संगठन के लिये काम कर रहे हैं। आज जब डॉ. सुशांत, निक्का सिंह पटियाल और अनूप केसरी जैसे लोग पार्टी का अध्यक्ष बनकर छोड़ कर चले गये हैं ऐसे में सुभाष जैसे व्यक्ति पर पार्टी की नजर न जाना भी पार्टी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है।